"recognised public hospitals', reimbursement made for treatment in that hospital will not be treated as a perquisite.

Monthly checks on Central Government Expenses

515. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what kind of monthly checks Government propose to control Government expenses;

(b) whether it will help in reducing the expenses and if so, what are the details thereof ; and

(c) how much expenses have been incurred so far for organising these monthly checks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) to (c) : Finance Minister has written to dlljMinisters suggesting identification of savings in estblishment expenditure so as to absorb the liability on account of fresh D.A. instalments. They have also been requested to draw up a quarterly/ monthly Budgets of expenditure and receipts, so as to facilitate monitoring of the over-all Budget Deficit. This exercise should not involve any additional expenditure.

राजस्थान में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

516. डा. अबरार अहमद खान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी कपड़ा मिलें स्थापित की गई हैं और वर्तमान में उनमें से कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार उन मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है और इन मिलों के कब तक चालू होने की संभावना है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में हथकरघा बुनकरों को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और वर्तमान में राजस्थान में हथकरघों की संख्या कितनी है ?

वस्त्र मंत्री, साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) 31-3-1990 की स्थिति अनुसार राजस्थान में 24 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों में से पांच बन्द पड़ी थी। इनमें से 4 मिलें वित्तीय संकट के कारण बन्द थी और एक मिल कामगारों की हड़ताल की वजह से बन्द थी।

(ख) बन्द/रूग्ण वस्त्र मिलों का पुन-रुद्धार नौडीय अभिकरण बी आई एफ आर के समक्ष उनकी अर्थ क्षमता के प्रमाणित होने पर निर्भर करता है जिसकी स्थापना सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए की है।

(ग) वर्ष 1987-88 की राष्ट्रीय गणना के अनुसार राजस्थान में 33,256 हथकरघा थे। केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए 22 मदों को आरक्षित किया है। मिल गेट कीमतों पर बुनकरों को यार्न की सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय हथ-करघा विकास निगम ने यार्नडिपों स्थापित किए हैं। करघा पूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधायें स्थापित करने, आधु-निकीकरण व नवीकरण के लिए सहायता देने तथा करघों की खरीद आदि के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना, जनता कपड़ा योजना, बचत निधि योजना के जरिए भी बुनकरों को सहायता प्रदान की जा रही है।